(b) if so, what action have Government taken thereon;

(c) whether it is a fact that the BEL has the potential to develop TV Glass, Shells; and

(d) if so, whether it is also a fact that they can also produce the TV Glass Shells in combination with NEG-BEL?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Yes, Sir.

(b) The representations from the BEL Taloja Save Forum, Talojo, requested Government not to approve any proposal from M/s. JCT Electronics Ltd. and its Japanese partner M/s. NEG to set up a unit for the production of B&W TV Glass Shells as this would be against the interests of Bharat Electronics. It was further suggested that when such a proposal is received NEG may be advised to have a joint venture with Bharat Electronics for expansion/Introduction of colour technology at the Taloja unit.

In the above context, it is clarified that so far Government have not received any proposal from JCT Electronics Ltd. for foreign collaboration with NEG Japan for manufacture of B&W TV glass shels. If such a proposal is received, it will be considered in accordance with prescribed procedure. It is also mentioned that at present there is no proposal to introduce colour glass technology at BE's Taloja Unit. As such, the question of setting up a joint venture by the company for this purpose with the M/s. NEG, Japan or any other foreign collaborator does not arise.

(c) and (d) Bharat Electronics is already manufacturing Glass Shells for Black and White picture tubes.

Panel on the Working of Doordarshan

1670. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) Whether Government propose to constitute panels in regard to the working of Doordarshan; and

(b) if so, the details thereof together with the guidelines to nominate the members of the panel?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) No, Sir. There is no proposal at present to constitute panels in regard to the working of Doordarshan.

(b) Does not arise.

उत्तरी बिहार में प्रकाशित नकली दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकायें

1671. श्री राम अवधेश सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार में अनेक नकली दैनिक समाचार-पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है जिनके लिए अखबारी-कागज का कोटा प्राप्त कर लिया जाता है और उसे काला-बाजार में बेच दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे पत्र और पत्रिकायें सरकार या सरकारी-क्षेत्र के उद्योगों से लाखों रुपये के विज्ञापन प्राप्त कर रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की 50-100 प्रतियां प्रकाशित करके, ऐसे व्यक्ति इस आशय के जाली दस्तावेज तैयार कर लेते हैं कि उनके द्वारा समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की हजारों और लाखों प्रतियों का प्रकाशन किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा और समस्तीपुर स्थित ऐसे प्रकाशनों पर छापे मारेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशक की प्रामाणिकता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित की जाती है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस बारे में कोई विशिष्ट जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समाचारपत्रों को विज्ञापन दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) किसी विशिष्ट उदाहरण के अभाव में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

उर्वरक-वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए रेक प्वाइंट का खोला जाना

1672. **श्री सुरेश पचौरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में रेक-प्वाइंट खोलने के क्या मानदंड हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार उर्वरक वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त रेक प्वाइंट खोलने पर विचार कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसे कितने अतिरिक्त रेक-प्वाइंट खोले जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) अर्थव्यवस्था रेक प्वाइंट खोलने के लिए मूल मानदण्ड को न्यूनतम परिवहन लागत प्रदान करना है। रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार रेक प्वाइंट द्वारा लगभग 100 कि०मी० तक के भीतरी प्रदेश की सेवा प्रदान करनी चाहिए और प्रत्येक रेक प्वाइंट के लिए पर्याप्त उर्वरक का आवागमन होना चाहिए ताकि प्रत्येक सप्ताह दो या अधिक रेक प्राप्त कर सके।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में और रेक संचालन प्वाइंट खोलने के लिए विकास कार्य प्रगति पर है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Stenographers in the Ministry of Personnel

1673. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Stenographers in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;

(b) whether the quota reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes has been completed;

(c) if not, what steps being taken by Government to complete that quota; and

(d) when the reservation quota is proposed to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) 127.

(b) to (d) Stenographers in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension are borne on a common cadre controlled by the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs appoint and post stenographers to the various cadre units controlled by it including Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions. The prescribed quota of vacancies is kept reserved for candidates belonging to SC/ST by the Cadre Controlling authority as a whole but the posting in the cadre units is not strictly based on quota for the respective units.

उर्वरकों पर राज-सहायता कम किए जाने का उर्वरकों की मांग पर प्रभाव

1674. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों पर राज सहायता को समाप्त कर देने से देश में उर्वरकों की मांग पर प्रभाव पड़ेगा ;